

दिल्ली उच्च न्यायालय: नई दिल्ली

मो.दु.दा. 1192/2012

निर्णय सुरक्षित: 9 मई, 2014

निर्णय उद्घोषित: 28 मई, 2014

रॉयल सुंदरम एलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड अपीलार्थी

के द्वारा: सुश्री सुमन बग्गा, अधिवक्ता
बनाम

विमला देवी एवं अन्यप्रत्यर्थीगण

के द्वारा: श्री एम.सी. प्रेमी, अधिवक्ता हेतु श्री जी.के.
सचदेवा, प्रॉक्सी अधिवक्ता

कोरम:

माननीय न्यायमूर्ति सुश्री दीपा शर्मा

निर्णय

1. इस मामले में बीमा कंपनी ने दिनांक 18 अगस्त, 2012 को 6,74,904 रुपये का मुआवजा देने के आदेश तथा दिनांक 22 सितम्बर, 2012 को 10,25,256 रुपये का मुआवजा देने के आदेश को इस अपील के माध्यम से चुनौती दी है।

2. ट्रक सं. डीएल 1एम 2691 के चालक के खिलाफ धारा 279/337/304-क भा.दं.सं. के तहत प्राथमिकी सं. 100/2010 दर्ज की गई थी। दिनांक 20 जून, 2010 को अनिल कुमार मृतक हंस राज के साथ दिल्ली कैंट फ्लाई ओवर के बाईं ओर फुटपाथ पर टहल रहे थे और उसके बाद वे फुटपाथ के बीच में खड़े एक पेड़ के कारण सड़क पर आ गए, जब अचानक एक ट्रक सं. डीएल-1एम-2691, जिसे उसका चालक बहुत तेज गति से, लापरवाही से, बिना कोई हार्न बजाए चला रहा था, ने पीछे से दोनों को टक्कर मार दी। दोनों को बेस अस्पताल, दिल्ली कैंट ले जाया गया और वहां से उन्हें डीडीयू अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। अनिल को उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई जबकि हंस राज को बालाजी एक्शन अस्पताल, पश्चिम विहार ले जाया गया। उसे मृत घोषित कर दिया गया। मृतक की उम्र 21 वर्ष थी और वह दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों का मामला यह है कि वह एक स्कूल बस में हेल्पर के रूप में काम करता था।

3. मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा भी प्रतिदावा दायर किया गया है, जिसके तहत उन्होंने अंतिम संस्कार व्यय के लिए 50,000 रुपए का दावा किया है। उपचार के लिए 10,000 रुपए दिए गए तथा मुआवजे में वृद्धि का दावा किया गया है।

4. विद्वान अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि दुर्घटना अपराधी वाहन के चालक द्वारा तेज गति और लापरवाही से गाड़ी चलाने का परिणाम थी और मृतक 21 वर्ष का था और स्नातक की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन इस बात का कोई सबूत नहीं था कि वह हेल्पर के रूप में काम कर रहा था। एक स्कूल बस में, उसकी आय को एक अकुशल श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी की अनुसूची के अनुसार लिया गया और निर्भरता के नुकसान की गणना की गई। इसके बाद, धारा 114 के तहत एक आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसे सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 के साथ पढ़ा गया, जिसमें बताया गया कि चूंकि मृतक मैट्रिक पास था, इसलिए न्यूनतम मजदूरी मैट्रिक पास की होनी चाहिए थी। उनके मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एक्स पीडब्लू1/ई और डिप्लोमा सर्टिफिकेट एक्स पीडब्लू1/सी रिकॉर्ड पर साबित हुए। इन दस्तावेजों के मददेनजर, विद्वान अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मैट्रिक पास व्यक्ति को न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए था और तदनुसार, निर्भरता के नुकसान की पुनर्गणना की और 10,25,256/- रुपये की राशि का आदेश दिया। दिनांक 18 अगस्त, 2012 के अपने पहले के आदेश के अनुसार, अधिकरण ने

6,74,904/- रुपये की राशि का आदेश दिया था। अधिकरण ने बीमा कंपनी पर मुआवज़ा देने की ज़िम्मेदारी भी तय की है।

5. अपीलार्थी ने विभिन्न आधारों पर इस पुरस्कार का विरोध किया है। पहला आधार यह है कि अधिकरण ने दिनांक 18 अगस्त, 2012 के पिछले आदेश को संशोधित करने में गलती की है और दिनांक 22 सितंबर, 2012 का एक आदेश था जिसे रद्द किया जाना चाहिए। अपीलार्थी के इस तर्क में कोई दम नहीं है क्योंकि अधिकरण को अपने आदेश की समीक्षा करने का अधिकार है यदि अधिकरण को लगता है कि रिकॉर्ड पर कोई स्पष्ट त्रुटि थी जिसे ठीक करने की आवश्यकता थी। 18 अगस्त, 2012 के अपने पहले के आदेश में, विद्वान अधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि मृतक स्नातक की पढ़ाई कर रहा था। यह तथ्य ही दर्शाता है कि मृतक मैट्रिक पास था, फिर भी आश्रितता की हानि की गणना करते समय मैट्रिक पास की न्यूनतम मजदूरी का उपयोग नहीं किया गया था। इसके बाद, जब समीक्षा के आवेदन में मैट्रिक पास होने के दस्तावेज और अन्य प्रासंगिक दस्तावेज अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किए गए, तो अधिकरण का कर्तव्य था कि वह गलती को ठीक करे। मुझे दिनांक 22 सितंबर, 2012 के विवादित निर्णय को रद्द करने का कोई कारण नजर नहीं आता।

6. अपीलार्थी का अगला तर्क यह है कि अधिकरण ने मृतक की आयु के अनुसार गुणक को गलत तरीके से लिया है। चूंकि मृतक 21 वर्ष का अविवाहित मो.दु.दा. 1192/2012

था और उसके माता-पिता जीवित हैं, इसलिए गुणक को माता-पिता की औसत आयु के अनुसार लिया जाना चाहिए था।

7. अपीलार्थी के तर्क में बल है। यह स्थापित कानून है कि गुणक मृतक या उत्तरजीवी की उम्र, जो भी अधिक हो, के अनुसार लिया जाना चाहिए। इस मामले में, उत्तरजीवी की आयु अधिक है और इसलिए, गुणक को माता-पिता की आयु के अनुसार लिया जाना चाहिए। माता-पिता की आयु लगभग 55 वर्ष थी। इसलिए, **सरला वर्मा बनाम डीटीसी 2009 एसीजे 129** के मामले को देखते हुए, आश्रितता की हानि की गणना करते समय 9 के गुणक का उपयोग किया जाना चाहिए था।

8. अपीलार्थी की ओर से यह भी तर्क दिया गया है कि अधिकरण ने गलत तरीके से भविष्य की संभावनाओं को मान्यता दी है, जबकि **सरला वर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) को ध्यान में रखते हुए वह किसी भी भविष्य की संभावनाओं का हकदार नहीं था। मृतक के विधिक प्रतिनिधिगण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि अधिकरण ने भविष्य की संभावनाओं को सही तरीके से मान्यता दी है, हालांकि, **सरला वर्मा** के मामले (पूर्वोक्त) को ध्यान में रखते हुए यह 50% होना चाहिए था क्योंकि मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी, जबकि अधिकरण ने 30% का इस्तेमाल किया है।

9. मैंने शीर्ष न्यायालय के निष्कर्षों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। सरला वर्मा (पूर्वोक्त) मामले में शीर्ष न्यायालय ने भावी संभावनाओं के अनुदान के लिए प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया है। इसने भावी संभावनाओं के लिए हकदार व्यक्तियों की श्रेणियों को वर्गीकृत किया है। प्रासंगिक पैराग्राफ निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किए गए हैं: -

"10. आम तौर पर मृतक की वास्तविक आय में से आयकर घटाकर मुआवजे की गणना के लिए शुरुआती बिंदु होना चाहिए। सवाल यह है कि क्या मृत्यु के समय वास्तविक आय को आय के रूप में लिया जाना चाहिए या भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोई जोड़ दिया जाना चाहिए। सुसम्मा थॉमस में, इस न्यायालय ने माना कि जीवन और करियर में उन्नति की भविष्य की संभावनाओं को भी गुणक (आश्रितों के लिए वार्षिक योगदान) को बढ़ाने के लिए धन के संदर्भ में देखा जाना चाहिए; और जहां मृतक के पास एक स्थिर नौकरी थी, न्यायालय भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रख सकती है और मृत्यु के समय मृतक की वास्तविक आय पर निर्भरता के नुकसान का अनुमान लगाना अनुचित होगा। उस मामले में, मृत्यु के समय 39 वर्ष की आयु के मृतक का वेतन 1032/- रुपये प्रति माह था। भविष्य की संभावनाओं के संबंध में साक्ष्य को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का विचार था कि व्यक्तिगत जीवन व्यय को घटाने से पहले सकल आय के रूप में 2000/- रुपये पर मासिक आय का उच्च अनुमान लगाया जा सकता है। सुसम्मा थॉमस के मामले में लिए

गए निर्णय का अनुसरण सरला दीक्षित बनाम बलवंत यादव [1996 (3) एससीसी 179] में किया गया, जहां मृतक को प्रति माह 1543 रुपये का सकल वेतन मिल रहा था। पदोन्नति और वेतन वृद्धि की भविष्य की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय ने माना कि जब तक वह सेवानिवृत्त होगा, तब तक उसकी कमाई लगभग दोगुनी हो गई होगी, मान लीजिए 3000 रुपये। इस न्यायालय ने मृत्यु के समय वास्तविक आय और यदि वह सामान्य जीवन जीता तो अनुमानित आय का औसत लिया और मासिक आय 2200 रुपये प्रति माह निर्धारित की। अबती बेजबरुआ बनाम उप महानिदेशक, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण [2003 (3) एससीसी 148] में, दुर्घटना के समय 42,000/- रुपये प्रति वर्ष (3500/- रुपये प्रति माह) की वास्तविक वेतन आय के मुकाबले, इस न्यायालय ने मृतक की भविष्य की संभावनाओं और कैरियर की उन्नति को ध्यान में रखते हुए, जो 40 वर्ष का था, आय को 45,000/- रुपये प्रति वर्ष माना।

"11. सुष्मा थॉमस मामले में, इस न्यायालय ने आय में लगभग 100% की वृद्धि की, सरला दीक्षित मामले में, आय में केवल 50% की वृद्धि हुई और अबती बेजबरुआ मामले में आय में केवल 7% की वृद्धि हुई। अनपेक्षित और अनिश्चितताओं को देखते हुए, हम एक सामान्य नियम के रूप में, मृतक की वास्तविक वेतन आय में भविष्य की संभावनाओं के लिए 50% वास्तविक वेतन जोड़ने के पक्ष में हैं, जहां मृतक के पास एक स्थायी नौकरी थी और वह 40 वर्ष से कम था। [जहां वार्षिक आय कर योग्य सीमा में है,

वहां 'वास्तविक वेतन' शब्दों को 'वास्तविक वेतन घटा कर' पढ़ा जाना चाहिए। यदि मृतक की आयु 40 से 50 वर्ष थी, तो जोड़ केवल 30% होना चाहिए। जहां मृतक की आयु 50 वर्ष से अधिक है, वहां कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। हालांकि साक्ष्य वृद्धि के एक अलग प्रतिशत का संकेत दे सकते हैं, लेकिन अलग-अलग मानदंडों को लागू करने या गणना के विभिन्न तरीकों को अपनाने से बचने के लिए जोड़ को मानकीकृत करना आवश्यक है। जहां मृतक स्वरोजगार कर रहा था या उसे निश्चित वेतन मिल रहा था (वार्षिक वेतन वृद्धि आदि के प्रावधान के बिना), वहां न्यायालय आमतौर पर मृत्यु के समय केवल वास्तविक आय ही लेगा। इससे अलग हटकर केवल दुर्लभ और असाधारण मामलों में ही निर्णय लिया जाना चाहिए।

विषय: प्रश्न (ii) - व्यक्तिगत एवं जीवन-यापन व्यय के लिए कटौती।”

10. सरला वर्मा केस (पूर्वोक्त) में दिए गए निर्देशों से यह स्पष्ट है कि केवल दो श्रेणियों के व्यक्ति भविष्य की संभावनाओं के हकदार नहीं हैं, एक, जहां मृतक स्व-रोजगार में था और दूसरे, जहां मृतक एक निश्चित वेतन (वार्षिक वेतन वृद्धि आदि की संभावना के बिना) पर काम कर रहा था।

11. शीर्ष न्यायालय ने सुषमा थॉमस मामले का संदर्भ दिया है जिसमें भविष्य की संभावनाएं एक मृतक को दी गई थीं, जिसके पास एक 'स्थिर नौकरी' थी। अन्य संदर्भित मामलों में भी, मृतक वेतनभोगी व्यक्ति थे। शीर्ष न्यायालय के

निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ने से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इसका उद्देश्य केवल दो श्रेणियों को बाहर करना था, यानी जहां मृतक स्व-नियोजित था या जहां वह वार्षिक वेतन वृद्धि आदि के प्रावधान के बिना एक निश्चित वेतन पर काम कर रहा था। आवश्यक निहितार्थ से, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि माननीय शीर्ष न्यायालय का इरादा उन वेतनभोगी व्यक्तियों को बाहर करने का नहीं है जो एक निश्चित वेतन पर कार्यरत नहीं हैं। इस प्रकार, शीर्ष न्यायालय का मतलब उन सभी व्यक्तियों को शामिल करना था जो रोजगार में हैं लेकिन एक निश्चित वेतन पर नहीं हैं।

12. वर्तमान मामले में, मृतक को एक दिहाड़ी मजदूर माना गया था। सरकार न्यूनतम मजदूरी में सालाना दो बार, यानी 1 फरवरी और 1 अगस्त को संशोधित करती है। इस प्रकार मृतक *सरला वर्मा केस (पूर्वोक्त)* में छूट प्राप्त श्रेणी में नहीं आता है। *सरला वर्मा केस (पूर्वोक्त)* के अनुसार, चूंकि मृतक की आयु 40 वर्ष से कम थी, इसलिए वह भविष्य की संभावनाओं के लिए अपने वेतन का 50% अतिरिक्त पाने का हकदार था।

क) मैट्रिक पास की न्यूनतम मजदूरी	रु. 6448
+ 50% भविष्य	रु. 6448 + 3224
	= रु. 9672

ख) व्यक्तिगत जीवन व्यय

पर 1/2 कटौती

$$\begin{aligned} & \text{रु. } 9672 - 4191 \\ & = \text{रु. } 5481/- \end{aligned}$$

ग) निर्भरता की हानि

$$\begin{aligned} & 5481 \times 12 \times 9 \\ & = \text{रु. } 591954/- \end{aligned}$$

13. प्रतिवाद में मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों ने तर्क दिया कि अधिकरण ने अंतिम संस्कार के खर्च के लिए मात्र 10,000 रुपये की मामूली राशि दी है। उन्होंने अंतिम संस्कार के खर्च के लिए 50,000 रुपये खर्च किए थे और उन्हें यह राशि मिलनी चाहिए थी। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने कहा कि अधिकरण ने अंतिम संस्कार के खर्च के लिए सही तरीके से राशि दी है।

14. शीर्ष न्यायालय ने 2013 (9) एस.सी.सी. 54 के **राजेश एवं अन्य बनाम राजबीर सिंह एवं अन्य** मामले में स्पष्ट किया है कि मुआवज़ा क्या है। प्रासंगिक पैराग्राफ़ इस प्रकार है:

"7. सरला वर्मा के मामले (पूर्वोक्त) में 'उचित मुआवज़ा' की व्याख्या की गई है, जिसमें कहा गया है कि अधिकरण द्वारा दिया गया मुआवज़ा सिर्फ़ इसलिए उचित नहीं हो जाता क्योंकि अधिकरण ने उसे उचित माना है। 'उचित मुआवज़ा' उचित मुआवज़ा है जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उचित और न्यायसंगत है, ताकि मुआवज़ा देने से संबंधित सुस्थापित सिद्धांतों को लागू

करके, जहाँ तक पैसे से ऐसा किया जा सकता है, गलत काम के परिणामस्वरूप हुए नुकसान की भरपाई की जा सके। लगभग सभी पिछले निर्णयों का सर्वेक्षण करने के बाद, न्यायालय ने मोटर दुर्घटना दावों में नुकसान के आकलन के मानदंडों को लगभग मानकीकृत कर दिया है।”

न्यायालय ने यह भी कहा है:

21. हम इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान भी ले सकते हैं कि अधिकरण ‘अंतिम संस्कार व्यय’ के अंतर्गत मुआवज़ा देने के मामले में काफी मितव्ययी रहे हैं। यह एक तथ्य है कि ‘मूल्य सूचकांक’ भी इस संबंध में बढ़ गया है। ‘अंतिम संस्कार व्यय’ शीर्षक का अर्थ श्मशान में भुगतान की गई फीस या कब्रिस्तान में जगह के उपयोग के लिए भुगतान की गई फीस नहीं है। अंतिम संस्कार के संबंध में कई अन्य खर्च होते हैं और यदि मृतक किसी विशेष धर्म का अनुयायी है, तो परिवार में मृत्यु के बाद कई धार्मिक प्रथाएं और परंपराएं होती हैं। ये सभी काफी महंगे हैं। इसलिए, हमारा मानना है कि ‘अंतिम संस्कार व्यय’ शीर्षक के अंतर्गत, उच्च व्यय के विपरीत साक्ष्य के अभाव में, कम से कम 25,000/- रुपये की राशि देना उचित, निष्पक्ष और न्यायसंगत होगा।”

15. इसे देखते हुए, मैं अंतिम संस्कार व्यय के लिए 25,000/- रुपये की राशि प्रदान करता हूँ। मैं निम्नलिखित मुआवज़ा प्रदान करता हूँ।

1.	निर्भरता की हानि	रु. 5,91,948/-
2.	स्नेह का अलगाव	रु. 1,00,000/-
3.	अंतिम संस्कार के खर्च के लिए	रु. 25,000/-
4.	संपत्ति का नुकसान	<u>रु. 10,000/-</u>

कुल रु. 7,26,948/-

16. मैं याचिका दायर करने की तिथि से इसकी वसूली तक 9% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित 7,26,948/- रुपये की राशि प्रदान करता हूँ।

17. मुआवजा अधिकरण के दिनांक 22 सितम्बर, 2012 के निर्णय के अनुसार वितरित किया जाएगा।

18. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, अपील और प्रति-दावा का निपटान किया जाता है।

न्या. दीपा शर्मा

मई 28, 2014

आरबी

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।